RAJYA SABHA

Wedneday, the 18th August, 2004/27 *Sravana,* 1926 (*Saka)*

The House met at Eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*321.श्री पी. के. माहेश्वरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वर्ष 1992 से चलाये जा रहे केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम को, केवल पूर्ण सफाई अभियान कार्यक्रम के लिए स्वीकृत जिले में ही चलाने के निर्देशों के कारण, बंद कर दिया गया हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त कार्यक्रम में राज्य के 30 जिलों को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु परियोजनाएं भेजी हैं, और

(घ) यदि हां, तो स्वीकृति न प्रदान करने के क्या कारण हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

विवरण

(क) और (ख) संपूर्ण स्वच्छता अभियान नामक मांग-जनित घटक शुरू करके केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में आबंटन आधारित घटक को धीरे-धीरे कम किया गया और 1.4.2002 से पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब सिर्फ संपूर्ण स्वच्छता अभियान ही कार्यान्वयन के अधीन हैं।

(ख) और (घ) मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। परियोजनाओं के अंतिम समूह को जुलाई,2003 में स्वीकृत किया गया।

Central Rural Sanitation Programme

†321. SHRI P. K. MAHESHWARI: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Central Rural Sanitation Programme being run in Madhya Pradesh since 1992 has been discontinued due to instructions of running this programme only in the districts approved for total sanitation campaign programme;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Government of Madhya Pradesh has sent projects for approval to Central Government for 30 districts of the State for inclusion in the said programme; and

(d) if so, the reasons for not according the approval and by when Central Government are likely to accord sanction for the same?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) Central Rural Sanitation Programme (CRSP) was restructured by Government of India in 1999 by introducing a demand driven component, namely the Total Sanitation Campaign (TSC). In the restructured CRSP, the allocation based component was gradually reduced and completely phased out with effect from 1.4.2002, and only the Total Sanitation Campaign (TSC) is under implementation now.

(c) and (d) TSC projects in all the districts of Madhya Pradesh have been sanctioned by Government of India. The last batch of projects was sanctioned in July, 2003.

श्री विक्रम वर्मा : सभापति महोदय, एथेंस ओलम्पिक में हमारे एक खिलाड़ी ने पदक जीता हैं ....।

श्री सभापति : वह आ रहा हैं। आम तसल्ली रखिये।

श्री पी.के. माहेश्वरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इस योजना के तहत कितनी राशि मध्य प्रदेश को दी गई हैं?

†Original notice of the question was received in Hindi.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में कुल योजना 422 करोड़ रूपये की स्वीकृत हैं, जिसमें अभी तक 89.7 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार की ओर से दिये गये हैं। राज्य सरकार को उसमें 15.19 करोड़ रूपये और लाभार्थियों से 6.07 करोड़ रूपये खर्च करने हैं।

श्री पी.के. माहेश्वरी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो योजना हैं, यह गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोंगों के लिये हैं और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 10 परसेंट से अधिक हैं, तो क्या मंत्री महोदय इसके लिए दी जाने वाली धनराशि में कुछ और वृद्वि करने की मंशा रखे हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, इस सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को तीन तरह से कराया जाता हैं। एक, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सबसिडी दी जाती हैं और तब इंडिविजयुअल बेनीफिशियरीज का शौचालय बनाया जाता हैं। दूसरे, सामूहिक शौचालय बनाने का भी प्रंबध हैं, जिसमें लाभार्थी को भी कुछ अंशदान देना पड़ता हैं। तीसरे, तमाम विद्यालयों में भी शौचालय बनाने का प्रबंध किया गया हैं। इसको तीन तरह से किया गया हैं। माननीय सदस्य की रूचि ग्रामीण स्वच्छता अभियान के बारे में हैं। इसलिए उसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है जिससे स्वच्छता अभियान सफल हो सके। उसमें ऐसा प्रबंध किया जाता हैं जिससे देश के एक भी आदमी को बाहर शौचालय के लिए न जाना पड़े और उनके लिए शौचालयों का प्रबंध कर दिया जाये।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : माननीय सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो महत्वपपूर्ण बाते कहीं हैं। एक, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को सबसिड दी जाती हैं। नम्बर दो, विद्यालयों को शौचालय बनाने के लिए भी धनराशि दी जाती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को अभी तक कितनी सबसिडी दी गई हैं? मेरा दूसरा सवाल हैं, कितने विद्यालयों को शौचालय बनाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, यह प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। माननीय सदस्य का राज्यवार सवाल हैं या पूरे देश के लिए हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : आप मध्य प्रदेश के बारे में ही बता दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मध्य प्रदेश में जो इनडिविजुअल बेनीफिशरीज के लिए योजना हैं, वह 33 लाख 11 हजार 313 परिवारों के लिए योजना हैं कि इतने परिवारों के लिए इनडिविजुअल शौचालय बनवाएं जाएं जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर का अलग हैं और गरीबो रेखा से नीचे के लोगों का अलग हैं। फिर स्कूलों के टॉयलेट्स हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : यह अलग कितना हैं? सभापति महोदय, मैने पूछा हैं कि कितना हैं लेकिन मंत्री महोदय नम्बर नहीं बता रहे हैं। मैने नम्बर पूछा है। ....(व्यवधान)... मैंने दो बातें पूछी हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ....(व्यवधान)... महोदय, टोटल प्रोजेक्ट आउटले 422 करोड़ 54 लाख रूपए हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : यह तो पूरा आपने ...(व्यवधान)....

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जिसमें हम लोगों को केन्द्र सरकार से 79 करोड़ देना हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा। मैने हिन्दी में बहुत सीधा सा सवाल पूछा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हिन्दी में ही उत्तर दे रहा हूं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : वह आप बता नहीं रहे हैं। आप घुमा रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल पूछ लीजिए न।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : मैं फिर से पूछता हूं।

श्री बलबीर के.पुंज : महोदय, मंत्री महोदय अभी भी पूछ रहे हैं कि प्रश्न क्या हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : मैं फिर से पूछ रहा हूं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को सब्सिडी देने की बात आपने स्वच्छता अभियान में कहीं हैं। मध्य प्रदेश में कितने परिवारों को सब्सिडी दी गयी हैं और कितने विद्यालयों के लिए शौचालय बनाने के लिए आपने कितनी राशि मध्य प्रदेश में आबंटित की हैं? इन दो बातों का जवाब मुझे साफ-साफ चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मध्य प्रदेश का तो महोदय, पहले ही बता दिया।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : नहीं बताया हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : 79.72 करोड़ रूपये दिए गए हैं, यहां से। ....(व्यवधान)... वह तो पहले ही प्रश्न में हैं। ....(व्यवधान)... कुल 272 करोड़ की परियोजना हैं जिसमें से 79 करोड़ रूपए केन्द्र सरकार ने रिलीज कर दिये हैं।

श्री सभापति : एक और इन्हें बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में शौचालय कितने बनाए हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : विद्यालयों के शौचलयों ...(व्यवधान)...

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मध्य प्रदेश में अभी तक इनडिविजुअल बेनीफिशरीज के लिए ....(व्यवधान)..

श्री बलबीर के. पुंज : महोदय, मंत्री जी तैयार होकर नहीं होते हैं। आप इन्हें निर्देशित कीजिए कि तैयार होकर आएं।

श्री सभापति : वे तैयार होकर आए हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :1 लाख 20 हजार 951 इनडिविजुअल बेनीफिशरीज़ के लिए,51 हजार 511 गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों के लिए और 12 लाख 72 हजार 462 गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए बनाएं गए हैं। स्कूलों के लिए 9 हजार 114 और सभी मिलाकर 12 लाख 9 हजार 51 बनाए गए हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया हैं। ...(व्यवधान)...

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : चेयरमैन साहब, मैं उस सवाल को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि लड़कियों के जो स्कूल हैं, वहां शौचालय न होने की वजह से लड़कियां कितनी ड्रॉपआउट होती हैं और उड़ीसा में जिस स्कीम के तहत महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए, उससे ड्रॉआउट का रेट कम हो गया। क्या सरकार के सामने कोई ऐसी स्कीम हैं, खास तौर से लड़कियों के लिए पूरे देश में शौचालय बनाने की?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, सरकार की योजना हैं कि देश के तमाम विद्यालयों में, आठ लाख प्राइमरी विघालय हैं और उसके बाद मिडल सकूल तथा हाई स्कूल, सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पानी और पाखाना का इंतजाम कर दिया जाए। खास तौर से लड़कियों के लिए अलग और लड़को के लिए अलग, हर स्कूल में यह प्रबंध हैं। टोटल सेनीटेशन कैम्पेन, जो सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता अभियान हैं, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं कि सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पानी और पाखाना का इंतजाम कर दिया जाए।

श्री सभापति : श्री तारिक अनवर ...(व्यवधान)...

श्रीमती सविता शारदा : यह गलत हैं। अभी तक नहीं हुआ हैं। ....(व्यवधान)...

श्री बलबीर के पुंज : सभी स्कूलों में कर दिया गया हैं, ऐसा कहा गया हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सविता शारदा : कहीं पर भी नहीं हैं। किसी ग्रामीण .....(व्यवधान)...

श्री एस.एस. आहलुवालिया : सर, यह गलतबयानी हो रही हैं। अभी कोलकाता कारपोरेशन की रिपोर्ट आई हैं। कोलकत्ता कारपोरेशन के बारे में बंगाल विधान सभा के उनके ऐजुकेशन मिनिस्टर ने खुद कहा है कि 245 गवर्नमेंट ओन्ड स्कूलों में से सिर्फ 125 स्कूलों में ही संडास की व्यवस्था की जा सकी हैं, दूसरों में नहीं की जा सकी हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे देश में कर दिया हैं लेकिन मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूं। ..(व्यवधान)... आप कहिए कि प्रावधान किया हैं।

डा. रघवंश प्रसाद सिंह : हमने कहां कहा हैं कि सभी विद्यालयों में प्रबंन्ध कर दिया गया हैं? ...(व्यवधान)... हमने यह कहा हैं कि टोटल सैनिटेशन कैम्पेन में सभी विद्यालयों में पानी और पारखाने का प्रबंध करने के लिए योजना बना दी गई हैं। उसका कार्यान्वयन किया जा रहा हैं और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हैं।3744 करोड़ रूपए का उसमें प्रोजेक्ट बनाया गया हैं और महोदय, यह टोटल सैनिटेशन कैम्पेन 398 जिलों में था,जिसको बढ़ाकर नए 142 जिलों में और किया गया हैं और देश भर में करीब 66 जिलों में टोटल सैनिटेशन कैम्पेन के तहत सभी के लिए प्रबंध किया जा रहा हैं और मैं समझता हूं कि सन् 2005 तक सभी विद्यालयों में पानी-पाखाने का इंतजाम कर दिया जाएगा।

Expenditure incurred on the Security of VIP's

*322. SHRI TARIQ ANWAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government are considering to reduce the security provided to the hundreds of VIPs;

(b) if so, the details thereof;

(c) the total number of VIPs who have been provided with the security; and

(d) the total expenditure incurred on the security of VIPs annually?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SRIPRAKASH JAISWAL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

श्री तारिक अनवर : सभापति महोदय, यह सही हैं कि आज हमारे देश में आतंकवाद और उग्रवाद एक जटिल समस्या है और उसको ध्यान में रखकर अगर सुरक्षा प्रदान की जाती हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु आज हमारे देश में जो सरकारी सुरक्षा दी जा रही हैं और ली